1. जैविक और रासायनिक हथियार कन्वेंशन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सदस्यों ने रूस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है कि यूक्रेन जैविक हथियार विकसित कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC):

- यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता वाली एक बहुपक्षीय संधि है।
- CWC के लिए बातचीत 1980 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू हुई।
- इस कन्वेंशन का मसौदा सितंबर 1992 में तैयार किया गया था और जनवरी, 1993 में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रैल 1997 से प्रभावी हुआ।

जैविक हथियार कन्वेंशन:

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मज़बूत मानदंड स्थापित किया है।
- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन एवं भंडारण व उनके विनाश के निषेध पर कन्वेंशन" के रूप में जाना जाता है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन द्वारा इस कन्वेंशन पर बातचीत की गई थी।
- 10 अप्रैल, 1972 को इस पर हस्ताक्षर हुए तथा 26 मार्च, 1975 को लागू किया गया।

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

2. **भारत, कनाडा फिर से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) वार्ता प्रारंभ करेंगे**

चर्चा में क्यों?

- भारत और कनाडा ने पांचवीं व्यापार और निवेश पर मंत्रिस्तरीय वार्ता (MDTI) आयोजित की।
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की लघु व्यवसाय, निर्यात संवर्धन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री सुश्री मैरी एनजी ने MDTI की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।
- दोनों देशों के मंत्री **भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)** के लिए फिर से बातचीत शुरू करने तथा एक अंतरिम समझौते या **प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (EPTA)** पर विचार करने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हुए, जिससे दोनों देशों को प्रारंभिक वाणिज्यिक लाभ मिल सकता है।

प्रमुख बिंदु

- अंतरिम समझौते में वस्तु, सेवा, स्रोत नियम, सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार की तकनीकी बाधाओं तथा विवाद समाधान शामिल किया जाएगा और यह समझौता पारस्परिक रूप से सहमत अन्य क्षेत्रों को भी कवर करेगा।
- कनाडा भारतीय जैविक उत्पाद निर्यातों की सहायता के लिए कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) को अनुरूपता सत्यापन संस्था (CVB) का दर्जा देने के बारे में तेजी से काम करने पर भी सहमत हुआ।

कनाडा के साथ भारत के वर्तमान व्यापार संबंध:

- भारत कनाडा का 11वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और कुल मिलाकर 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

Important News: India

3. अमृत 2.0 के अंतर्गत 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज'

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य (MoHUA) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT-अमृत) 2.0 के अंतर्गत **'इंडिया वाटरपिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज'** का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- भारत के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप, स्टार्टअप्स को 'प्रौद्योगिकी भागीदार' के रूप में शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन को अमृत 2.0 के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- मिशन का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से विकसित होने के लिए जल/उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाना है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
- इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय 100 स्टार्ट-अप का चयन करेगा, जिन्हें अनुदान सहायता के साथ-साथ मेंटरशिप के रूप में 20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

अमृत (अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन) के बारे में:

- 25 जून 2015 को 500 शहरों में अमृत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य 500 चयनित अमृत शहरों में पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और सीवरेज कवरेज में पर्याप्त सुधार करना था।
- हाल ही में, सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षित शहर बनाना, सभी वैधानिक शहरों में पानी का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और 500 अमृत शहरों में सीवरेज / सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज प्रदान करना है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

4. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण

चर्चा में क्यों?

- लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला ने नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में **राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-2022 के तीसरे संस्करण** के समापन समारोह को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय युवा संसद, युवाओं को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से परिचित कराने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (NYPF) के बारे में:

- इसका आयोजन उन युवाओं के विचार जानने के लिए किया जाता है जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे।
- NYPF 31 दिसंबर, 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है।

- इस विचार से प्रेरणा लेते हुए, NYPF का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था।

स्रोत: PIB

5. "फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने (SPI)" की योजना

चर्चा में क्यों?

- फार्मास्युटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 25-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ **"फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने (SPI)"** की योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और MSME को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार के लिए आवश्यक सहायता के संदर्भ में बढ़ती मांग को पूरा करेगी।
- योजना के अंतर्गत, फार्मा क्लस्टर को सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा, SME और MSME की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों (WHO-GMP या अनुसूची-M) को पूरा करने के लिए छूट के साथ ब्याज दर या उनके पूंजीगत ऋणों पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में वृद्धि को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

फार्मा क्षेत्र से संबंधित योजनाएं:

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना
- बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना

स्रोत: PIB

6. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन राष्ट्र को समर्पित किया

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक भवन राष्ट्र को समर्पित किया और अपना पहला दीक्षांत भाषण दिया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) की स्थापना पुलिस, अपराध संबंधी न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न अंगों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी।
- सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे 2010 में गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अक्टूबर, 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया।

नोट: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया।

स्रोत: इंडिया टुडे

Important News: State

7. 2021 में स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष रैंक बरकरार रखी

चर्चा में क्यों?

- आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर और महाराष्ट्र पांचवे स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- आंध्र प्रदेश ने पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान हासिल किया।
- एक विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंक बरकरार रखी।
- 2020 में भी, आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया।

स्कोच समूह के बारे में:

- स्कोच ग्रुप भारत का अग्रणी थिंक टैंक है जो 1997 से समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपट रहा है।
- समूह की कंपनियों में एक परामर्श विंग, एक मीडिया विंग और एक धर्मार्थ फाउंडेशन शामिल हैं।
- SKOCH ग्रुप ने नई दिल्ली में 2021 के लिए SKOCH गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और ईमेल आर्टिकल प्रिंट आर्टिकल म्युनिसिपल स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है।

स्रोत: द हिंदू

Important News: Appointment

8. देबाशीष पांडा को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों?

- मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति ने **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** के अध्यक्ष के रूप में पूर्व DFS सचिव, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, देबाशीष पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- देबाशीष पांडा को शुरू में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
- पांडा ने दो साल के कार्यकाल के बाद इस साल 31 जनवरी को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव के रूप में पद छोड़ दिया था।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में:

- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।
- **स्थापना:** 1999
- **मुख्यालय:** हैदराबाद
- IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।

स्रोत: द हिंदू

9. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी को चार धाम परियोजना पैनल प्रमुख नियुक्त किया

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायमूर्ति एके सीकरी से आग्रह किया कि वह "चार धाम महामार्ग विकास परियोजना (चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना) के पूरे हिमालय घाटी पर संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने के लिए" गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने न्यायमूर्ति सीकरी से अनुरोध किया कि वह कार्यभार स्वीकार करें क्योंकि समिति के वर्तमान अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने पद छोड़ने का विकल्प चुना था।
- इस परियोजना में उत्तराखंड में चार पवित्र शहरों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ - को हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए 900 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- रवि चोपड़ा ने पहले 10 मीटर कैरिज वे की केंद्र की मांग का विरोध किया था और जोर देकर कहा था कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5.5 मीटर तक सीमित रखा जाए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस